



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 10, 2001/वैशाख 20, 1923

No. 228]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 2001/VAISAKHA 20, 1923

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2001

सा. का. नि. 330(अ).— केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2001 है।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. नोटेरी नियम, 1956 में,-
(i) नियम 2 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
'(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।'
(ii) नियम 8 में, उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
'(4क) समुचित सरकार, तारीख नौ मई 2001 से और उसके पश्चात् यथास्थिति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट नोटेरियों की संख्या से अनधिक नोटेरी नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु यह कि ऐसे नोटेरियों की संख्या को, जिनका व्यवसाय प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नवीकृत हो गया है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट नोटेरियों की कुल संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त किए गए नोटेरियों की कुल संख्या में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तारीख ११ मई 2001 से पूर्व नियुक्त नोटेरियों की संख्या अनुसूची में विनिर्दिष्ट नोटेरियों की संख्या से अधिक हो तो ऐसे नोटेरी, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस प्रकार नियुक्त बने रहेंगे।" ;

(III) नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

(नियम 8 (4क) देखिए)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संघ नियुक्त किए जाने राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वाले नोटेरियों की नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम संख्या नोटेरियों की अधिकतम संख्या

(1)	(2)	(3)
1. आंध्र प्रदेश	575	575
2. असम	575	575
3. बिहार	925	925
4. गुजरात	625	625
5. केरल	375	375
6. मध्य प्रदेश	1125	1125
7. तमिलनाडु	725	725
8. महाराष्ट्र	875	875
9. कर्नाटक	675	675
10. उड़ीसा	750	750
11. पंजाब	425	425
12. राजस्थान	800	800
13. उत्तर प्रदेश	1750	1750
14. पश्चिम बंगाल	450	450
15. जम्मू-कश्मीर	350	350
16. नागालैण्ड	200	200
17. हरियाणा	475	475
18. हिमाचल प्रदेश	300	300
19. मणिपुर	225	225

(1)	(2)	(3)
20. त्रिपुरा	100	100
21. मेघालय	175	175
22. सिक्किम	100	100
23. मिजोरम	200	200
24. अरुणाचल प्रदेश	325	325
25. गोवा	50	50
26. उत्तरांचल	325	325
27. छत्तीसगढ़	400	400
28. झारखंड	450	450
29. दिल्ली	225	225
30. अण्डमान	50	50
और निकोबार द्वीपसमूह		
31. लक्षद्वीप	25	25
32. दादरा और नगर हवेली	25	25
33. दमन और दीव	50	50
34. पांडिचेरी	100	100
35. चंडीगढ़	25	25

[फ़. सं. 5(271)/2000-एन सी]

ब्रह्म अवतार अग्रवाल, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

टिप्पण:—मूल नियम का.नि.आ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्तवर्ती संशोधन सा.का.नि. 370(अ) तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547 (अ) तारीख 31 अगस्त, 1998, सा०का०नि० 17(अ) तारीख 5 जनवरी, 2000, सा०का०नि० 262 (अ) तारीख 28 मार्च, 2000, सा०का०नि० 630 (अ) तारीख 21 जुलाई, 2000 और सा०का०नि० 172(अ) तारीख 12 मार्च, 2001 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2001

G.S.R. 330(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2001.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956,-

- (1) in rule 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

'(d) "Schedule" means the Schedule appended to these rules.'

- (ii) in rule 8, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4A) The appropriate Government may on and after the ninth day of May, 2001, appoint notaries in a State or Union territory, as the case may be, not exceeding the number of notaries specified in the Schedule:

Provided that the number of notaries whose certificate of practice has been renewed under sub-section (2) of section 5 of the Act shall be included in the total number of notaries appointed for the purpose of counting the total number of notaries specified in the Schedule.

Provided further that if in a State or Union territory the number of notaries appointed before the ninth day of May 2001 exceeds the number of notaries specified in the Schedule, such notaries shall continue to be so appointed in that State or Union territory, as the case may be.";

(iii) after rule 13, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"THE SCHEDULE
[See rule 8(4A)]

Name of State/Union territory	Maximum number of notaries to be appointed by the Central Government	Maximum number of notaries to be appointed by State Government or Union territory Administration
(1)	(2)	(3)
1. Andhra Pradesh	575	575
2. Assam	575	575
3. Bihar	925	925
4. Gujarat	625	625
5. Kerala	375	375
6. Madhya Pradesh	1,125	1,125
7. Tamil Nadu	725	725
8. Maharashtra	875	875
9. Karnataka	675	675
10. Orissa	750	750
11. Punjab	425	425
12. Rajasthan	800	800
13. Uttar Pradesh	1,750	1,750
14. West Bengal	450	450
15. Jammu & Kashmir	350	350
16. Nagaland	200	200
17. Haryana	475	475
18. Himachal Pradesh	300	300
19. Manipur	225	225
20. Tripura	100	100
21. Meghalaya	175	175
22. "	100	100

(1)	(2)	(3)
23. Mizoram	200	200
24. Arunachal Pradesh	325	325
25. Goa	50	50
26. Uttaranchal	325	325
27. Chhattisgarh	400	400
28. Jharkhand	450	450
29. Delhi	225	225
30. Andaman and Nicobar Islands	50	50
31. Lakshadweep	25	25
32. Dadra and Nagar Haveli	25	25
33. Daman & Diu	50	50
34. Pondicherry	100	100
35. Chandigarh	25	25."

[F. No 5(271)/2000-NC]

BRAHM AVTAR AGRAWAL, Jt. Secy. and Legal Adviser

Note:- The principal rules were published vide S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and subsequently amended vide G.S.R.370(E), dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547 (E) dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E) dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262 (E) dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E) dated the 21st July, 2000 and G.S.R. 172 (E) dated the 12th March, 2001.